कोटद्वार, मंगलवार
3 फरवरी 2026
वर्षः 48
अंकः 251 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नरेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोन: 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

मसूरी में बाहरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा होम स्टे का लाइसेंस

देहरादून। मसूरी होम स्टे एसोसिएशन की एक बैठक में कई प्रस्ताव पास किए गए। मसूरी में किसी बाहरी व्यक्ति को होम स्टे का लाइसेंस नहीं देने दिया जाएगा।फरवरी के अंत तक शीघ्र कार्यकारणी का गठन करने पर सहमति बनी। सोमवार को मसूरी होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत की अध्यक्षता में बैठक लंढौर में हुई। बैठक में होम स्टे संचालकों की समस्याओं को सुना गया व कई प्रस्ताव पास किए गए। बैठक में होम स्टे संचालकों ने अपनी समस्याएं व सुझाव रखे। प्रस्ताव पास किया गया कि होम स्टे का लाइसेंस की समयावधि पांच वर्ष की जाए। कार्यकारणी का चुनाव फरवरी अंत तक आम सभा की बैठक में किया जाएगा। होम स्टे का लाइसेंस बाहरी व्यक्तियों को नहीं देने दिया जाएगा व होम स्टे में कमरों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव पास किया गया। होम स्टे एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र रावत ने कहा कि कार्यकारिणी बनाये जाने के बाद संस्था का नवीनीकरण किया जा सके। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों को होम स्टे का लाइसेंस देने का कड़ा विरोध किया जाएगा। प्रदेश सरकार का निर्णय भी है कि होम स्टे योजना स्थानीय लोगों के लिए है, इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में देवी गोदियाल अध्यक्ष बनाए गए थे व तीन वर्ष के लिए चुनाव हुआ था लेकिन कोरोना होने के कारण पांच वर्ष तक वह अध्यक्ष रहे। सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणी की जा रही है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके समाधान के लिए वरिष्ठ सदस्यों को जिम्मेदारी दी गयी है ताकि संगठन मजबूती से कार्य कर सके। उन्होंने होम स्टे टैरिफ पर कहा कि जो सरकार के मानक है उससे बाहर कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इसी माह के अंत तक कार्यकारिणी का चुनाव आम सभा में सभी की सहमति से किया जाएगा। उन्होंने होम स्टे संचालकों को भरोसा दिया कि उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा व जो सुझाव आएंगे उनका अनुपालन किया जायेगा।

एक साल में ही उखड़ गया संग्राली मोटर मार्ग का डामर

उत्तरकाशी। वरुणावत पर्वत के शीर्ष पर स्थित संग्राली गांव को जोड़ने वाले संग्राली मोटर मार्ग पर पिछले साल हुआ डामरीकरण उखड़ने लगा है। एक जगह पर तो सड़क पर बड़ा गड्ढा भी हो गया है जो आए दिन हादसे को न्योता दे रहा है। ग्रामीणों ने डामरीकरण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए विभाग से जल्द मार्ग के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग भटवाड़ी के अधिकारियों का कहना है कि सड़क पर बने गड्ढे और क्षतिग्रस्त दीवार निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई और एक दो दिन के भीतर सड़क सुधारीकरण का काम चालू हो जाएगा। जिला मुख्यालय से करीब 12 किमी दूर संग्राली गांव को जोड़ने वाला संग्राली मोटर मार्ग पर गड्ढा लंबे समय से बना है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर दीवार भी क्षतिग्रस्त है। संग्राली मोटर मार्ग न सिर्फ ग्रामीणों की आवाजाही का साधन है बल्कि यहां वरुणावत पर वी–टॉप के नाम से प्रचलित पर्यटक स्थल के दीदार को हर दिन सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। पूर्व प्रधान संदीप सेमवाल ने बताया कि पिछले साल ही विभाग ने सड़क पर डामरीकरण का कार्य करवाया था लेकिन सड़क की हालत बता रही है कि खराब गुणवत्ता की पेंटिंग इसमें हुई है। लोनिवि भटवाड़ी के अधिशासी अभियंता नवीन लाल वर्मा का कहना है कि सड़क के क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक करने के लिए ठेकेदार मंगलवार या बुधवार से काम शुरू कर देगा।

इंडिगो की दिल्ली–पंतनगर की दूसरी उड़ान रद

रुद्रपुर। सोमवार को पंतनगर एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के चलते इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली–पंतनगर की दूसरी निर्धारित उड़ान रद कर दी गई। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट निदेशक पवन कुमार ने बताया कि उड़ान संख्या 6ई–7156 को शाम 4:15 बजे पंतनगर पहुंचना था, लेकिन मौसम संबंधी दिक्कतों के कारण उसे रद करना पड़ा। प्रभावित यात्रियों को कंपनी की ओर से अगली उपलब्ध उड़ानों में समायोजित करने अथवा पूर्ण किराया वापस लेने का विकल्प दिया गया।

टैरिफ हटाएंगे ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को किया फोन

नई दिल्ली ,अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस बातचीत की जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने साझा की। दोनों नेताओं के बीच भारत–अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय सहयोग और वैश्विक मुद्दों पर विचार–विमर्श हुआ। अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर साझा की।

इंडिया गेट की तस्वीर के साथ ट्रंप ने क्या लिखा?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई दिल्ली स्थित इंडिया गेट की तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। इसके साथ ही इसे उन्होंने भारत का खूबसूरत विजय द्वार बताया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल ट्रुथ पर इंडिया गेट की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, भारत का खूबसूरत विजय द्वार। हमारा वाला सबसे महान होगा! 42 मीटर उंचा इंडिया गेट एक आर्क–डी–ट्रायम्फ है, जो प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय आंग्ल–अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हुए करीब 70,000 भारतीय सैनिकों की स्मृति में बनाया गया है।

टैरिफ के कारण दोनों देशों के संबंधों में तनाव

बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चल रहा है। हालांकि, दोनों देशों के बीच अहम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। अमेरिकी ने पिछले साल रूस के भारत द्वारा तेल खरीद को लेकर टैरिफ लगा दिए थे। जिसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव आ गया था। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले पीएम मोदी से बीते साल अक्तूबर में बातचीत की थी। ट्रंप ने पीएम मोदी को फ़ोन कर उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी थीं।

सड़क किनारे खंभे से टकराई मोटर साइकिल, युवक की मौत

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत सिगड्डी क्षेत्र में एक मोटर साइकिल सड़क किनारे खड़े विद्युत खंभे से टकरा गई। दुर्घटना में मोटर साइकिल चला रहे युवक की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार देर रात की है। मोटसाइकिल सवार झंडीचौड़, उत्तरी निवासी शमशेर सिंह बिष्ट (26) जशोधरपुर से अपने घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान अचानक लोकमणिपुर के समीप उसकी मोटर साइकिल अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े खंभे से टकरा गई। जिससे शमशेर के सिर पर गंभीर चोट लग गई और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। असपास मौजूद लोगों ने घायल शमशेर को राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कण्वघाटी चौकी प्रभारी राजाराम डोभाल ने बताया कि शमशेर सिंह ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। यदि उसने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच सकती थी।

केंद्रीय बजट विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप : धामी

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बलवीर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित मीडिया प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, निर्यात, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित होगा और राज्य के समावेशी, संतुलित व सतत विकास की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय में की गई बढ़ोतरी से दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के साथ-साथ भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और संप्रभुता को भी सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट के तीन प्रमुख स्तंभ-संतुलित एवं समावेशी विकास, वंचित वर्गों का क्षमता निर्माण और सबका साथ-सबका विकास-दूरस्थ के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों, गांवों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, बच्चों और वंचित वर्गों सभी के समग्र उत्थान का स्पष्ट मार्ग प्रशस्त करते हैं। उन्होंने बताया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों के विकास से उत्तराखंड के देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी जैसे शहरों को विशेष लाभ मिलेगा। प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' और 'विश्वास आधारित शासन' से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में किए गए विविध और नीतिगत प्रावधानों से उत्तराखंड में रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे।

आयुष, फार्मा, हथकरघा, खादी और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी। ग्रीन एनर्जी पर विशेष फोकस से उत्तराखंड जैसे पर्वतीय एवं वन संपदा से समृद्ध राज्य में ग्रीन इकोनॉमी को बल मिलेगा।

उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल माध्यम से पत्रकारों को किया सम्बोधित

देहरादून। केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री व इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी देहरादून) में आयोजित वर्चअल प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों के पत्रकारों को रेलवे बजट के संदर्भ में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस बार रेलवे को रिकॉर्ड 2.93 लाख करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय का बजट आवंटन किया गया है। इस आवंटन के लिए वैष्णव ने केंद्रीय वित्त मंत्री का भी आभार जताया है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बजट आवंटन का लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। वैष्णव ने कहा कि 2009 से 2014 तक सिर्फ 187 करोड़ का बजट उत्तराखंड में रेलवे के काम के लिए आवंटित किया गया था। जबकि रेल बजट (2026–27) में उत्तराखंड को रिकॉर्ड (26 गुना अधिक रेल बजट) 4 हजार 769 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। उत्तराखंड में कुल 39,491 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पर काम चालू है और इस बड़े निवेश में राज्य में ट्रैक बनाना, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सुरक्षा बढ़ाना शामिल है। अमृत स्टेशन योजना के तहत उत्तराखंड में कुल 11 स्टेशनों को पूरी तरह से रीडेवलप करने के लिए चयनित किया गया है। स्टेशन के आधुनिकरण के लिए 147 करोड़ का कुल निवेश किया जा रहा है। बेहतर कनेक्टिविटी, प्रीमियम ट्रेन सेवाओं के विस्तार के अंतर्गत राज्य में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं चल रही हैं और 1 अमृत भारत एक्सप्रेस की सेवा चालू है। नेटवर्क विस्तार और 100% विद्युतीकरण के मामले में उत्तराखंड में रेलवे नेटवर्क तेज़ी से बढ़ा है। 2014 से अब तक लगभग 76 ¹ ट्रैक का निर्माण किया जा चुका है। राज्य ने रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल कर लिया है जबकि 2014 से अब तक 334 ¹ रेल लाइनों को इलेक्ट्रिफाई किया जा चुका है और 106 फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए गए। रेलवे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब तक कुल 54 कवच स्वीकृत किए जा चुके हैं।

ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर बहुत तेजी से आगे काम बढ़ रहा है और जल्द ही ये अपने उद्घाटन की ओर बढ़ रही है।

महोत्सव के विरोध में व्यापारियों ने किया बाजार बंद

उत्तरकाशी। चौंड में आयोजित सात दिवसीय नगर महोत्सव के विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद रखकर शहीद स्मारक में धरना दिया। व्यापारियों ने नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मेला स्थगित करने की मांग की। तहसील प्रशासन ने नगर पंचायत अध्यक्ष व व्यापारियों से वार्ता की। विरोध को देखते हुए नगर पंचायत अध्यक्ष ने मेला सात के बजाय अब पांच ही दिन करने का आश्वासन दिया। लंबगांव नगर पंचायत की ओर से चौंड में एक से सात फरवरी तक नगर महोत्सव शुरू किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि महोत्सव/मेले को लेकर व्यापारियों को विश्वास नहीं लिया गया है। मेले में लगाए गए स्टाल भी बाहर के व्यापारियों को आवंटित किए गए हैं। व्यापारियों ने सोमवार को बाजार बंद कर शहीद स्मारक पर एकत्रित होकर धरने पर बैठे और नगर पंचायत के खिलाफ नारेबाजी कर मेला स्थगित करने की मांग की। तहसीलदार आनंदपाल व्यापारियों से वार्ता करने पहुंचे लेकिन व्यापारियों ने उनकी एक नहीं सुनी और चक्काजाम करने लगे।

मृत व्यक्ति के स्पर्म पर किसका हक? दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को केंद्र ने दी चुनौती

नई दिल्ली ,केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एक निजी अस्पताल को अविवाहित मृत व्यक्ति के 'फ्रीज् शुक्राणु उसके माता–पिता को सौंपने का निर्देश दिया गया था। चीफ जस्टिस डी. के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने केंद्र की याचिका पर मृतक के माता–पिता को नोटिस जारी किया है।

केंद्र ने सिंगल जज के 2024 के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि यदि शुक्राणु या अंडाणु के मालिक की सहमति स्पष्ट रूप से साबित हो जाए, तो मृत्युपरांत प्रजनन के लिए इनके इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। बेंच ने इस याचिका की आगे की सुनवाई के लिए 27 फरवरी 2026 की तारीख तय की है।

केंद्र का कहना है : मौजूदा कानून के विपरीत

सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि सिंगल जज का आदेश सहायक प्रजनन और सरोगेसी कानून के मौजूदा प्रावधानों के खिलाफ है। वकील ने बताया कि कानून में दादा–दादी को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और सरोगेसी के मकसद से इच्छुक दंपति बनने की अनुमति नहीं देता। उन्होंने यह भी कहा कि सिंगल जज के निर्देश के बावजूद मृतक का फ्रीज किया गया शुक्राणु अभी तक माता–पिता को नहीं सौंपा गया है, और इस पर दायर अवमानना याचिका अभी भी हाई कोर्ट में लंबित है। अदालत ने केंद्र से यह भी पूछा कि अपील दाखिल करने में एक साल से अधिक का विलंब क्यों हुआ।

2024 में सिंगल जज का आदेश

सिंगल जज की बेंच ने 4 अक्टूबर 2024 को सर गंगा राम अस्पताल को निर्देश दिया था कि मृतक का फ्रीज शुक्राणु उसके माता–पिता को सौंपा जाए। न्यायाधीश ने यह आदेश माता–पिता की याचिका पर दिया था और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भी यह विचार करने के लिए कहा था कि मृत्युपरांत प्रजनन से जुड़े मामलों पर कानून, अधिनियम या दिशा–निर्देश की आवश्यकता है या नहीं।

मामले की पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं के बेटे ने 2020 में कैंसर के इलाज से पहले स्पर्म का सैंपल फ्रीज करवा लिया था। डॉक्टरों ने बताया था कि कीमोथेरेपी प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए जून 2020 में उसने अस्पताल की ह्यूमन लेबोरेटरी में अपने स्पर्म सुरक्षित रखने का फैसला किया। सिंगल जज ने अपने फैसले में कहा था कि स्पर्म का सैंपल संपत्ति की तरह है और मृत व्यक्ति के मामले में यह मानव अंग या जैविक सामग्री का हिस्सा माना जा सकता है। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता के बेटे ने स्पष्ट रूप से सहमति दी थी कि वह अपने प्रजनन क्षमता बचाने के लिए स्पर्म फ्रीज करने के लिए तैयार है।

हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा 3.7 करोड़ के पार पहुंचा

– दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री के हाथों हुई थी हाउस आफ हिमालयाज की लांचिंग

देहरादून। पहाड़ की महिलाओं की मेहनत तैयार विशुद्ध उत्तराखंडी उत्पादों का ब्रांड 'हाउस ऑफ हिमालयाज', लांचिंग के दो साल के भीतर साढ़े तीन करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री करने में कामयाब रहा है।

जल्द ही हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद विदेशों में भी बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। ग्राम्य विकास विभाग के अधीन, हाउस ऑफ हिमालयाज, उत्तराखंड के महिला स्वयं सहायता समूहों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों और ग्रामीण उद्यमियों द्वारा बनाए गए उत्पादों का कॉमन ब्रांड है। इसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, दिसंबर 2023 के दौरान देहरादून में आयोजित ग्लोबल इंवेस्टर समिट के दौरान हुआ था। प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन के बाद हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की एकाएक मांग बढ़ी है। बीते दो साल में कुल बिक्री का आंकड़ा 3.7 करोड़ के पार पहुंच गया है। अब हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के उत्पाद ऑफलाइन के साथ ही ई कामर्स साइट जियो मार्ट, अमेजन, ब्लिंकिट, बिग बास्केट और ब्रांड की खुद की अपनी वेबासइट पर भी मिल रहे हैं।

50 विशिष्ट उत्पाद शामिल : वर्तमान में इस ब्रांड में कुल 50 उत्पादों को शामिल किया गया है। इसमें मिलेट्स बिस्किट, मुन्स्यारी, चकराता, हर्षिल की राजमा, चौलाई, तोर दाल, पहाड़ का परंपरागत लाल चावल, झंगोरा, गहथ, काले भट्ट, चाय, तेल, पर्सनल केयर, हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद शामिल हैं। इसके उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तीन स्तरों पर की जा रही है। सरकार स्थानीय मेलों, त्यौहार के मौकों पर हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों को खरीदने पर जोर दे रही है। साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और कार्यालयों के जरिए भी बिक्री बढ़ाने की रणनीति तैयार की गई है। दिवाली जैसे त्यौहार के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज की ओर से खास गिफ्ट पैक उपलब्ध कराए गए थे, जिन्हें खूब पसंद किया गया।

तीन हजार से महिलाओं को रोजगार : हाउस ऑफ हिमालयाज में अब तक कुल 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत किए जा चुके हैं। इस उत्पाद श्रंखला से राज्य की 3,300 से अधिक ग्रामीण महिलाएं प्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं। जबकि व्यापक क्रम नेटवर्क के माध्यम से 28,000 से अधिक महिलाओं को इसका अप्रत्यक्ष लाभ मिला है। ये उत्पाद प्रमुख शहरों में 26 आउटलेट्स के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इसमें जौलीग्रांट एयरपोर्ट का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट शामिल है। इसके साथ ही प्रतिष्ठित होटल श्रृंखलाओं एवं यात्रा केंद्रों में भी हाउस ऑफ हिमालयाज की प्रीमियम काट्र्स स्थापित किए गए हैं। साथ ही चार धाम मार्ग पर 10 फ्लोर स्टैंडिंग यूनिट्स तैनात की गई हैं।

जम्मू–कश्मीर में लगे भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 रही तीव्रता, लोग घरों से बाहर निकले

श्रीनगर , कश्मीर घाटी में सोमवार को मध्यम तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.8 मापी गई। लेकिन, इसका असर दूर–दूर तक हुआ क्योंकि इसका केंद्र बडगाम जिले में था। आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के अधिकारियों ने बताया कि भूकंप सुबह 5.35 बजे आया था और इसका केंद्र घाटी के बडगाम जिले में था। भूकंप ने कश्मीर को हिला दिया, क्योंकि इसका केंद्र घाटी में ही बडगाम में था, जो राजधानी श्रीनगर से सिर्फ 21 किमी उत्तर में है। लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकले क्योंकि भूकंप के झटकों से खिड़कियां और दरवाजे हिलने लगे थे। अधिकारी फिलहाल संभावित नुकसान या संपत्ति को हुए नुकसान के बारे में रिपोर्ट इक्ठा कर रहे थे। भूकंप के झटके 8 अक्टूबर 2005 को आए बड़े भूकंप की याद दिला रहे थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.6 थी, जिसे बहुत ज्यादा माना जाता है। उस भूकंप का केंद्र पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद शहर में था। वह भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसका असर दूर ताजिकिस्तान, शिनजियांग और अफगानिस्तान तक महसूस किया गया।

दो हत्याओं के बाद बिनारसी गांव छावनी में तब्दील

रुड़की। थाना क्षेत्र के ग्राम बिनारसी में हुए खौफनाक दोहरे हत्याकांड के बाद सोमवार को पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। बिनारसी गांव छावनी में तब्दील नजर आई। चारों तरफ पुलिस फोर्स के अलावा कोई नजर नहीं आया। पूरे दिन लोग अपने घरों में दुबके रहे। कई लोगों ने अपनों बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजा। इस गांव में रविवार को रविदास जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया था। पुरानी रंजिश को लेकर यहां दो पक्षों में बवाल हो गया। पथराव के बाद यहां गोली चलाने और लाठी डंडों से किए गए हमले में दो लोगों आनंद और मांगेराम की हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड के बाद गांव में और बवाल हो गया। एक पक्ष ने दूसरे के घरों में आग तक लगा दी। इधर, इस घटना के बाद पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हुए माहौल को शांत कराने के प्रयास में जुट गई। पूरी रात पुलिस फोर्स क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए तैनात रही। सोमवार को दोनों शवों का पंचनामा करने के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके बाद एक शव को गांव ले जाया गया। पहले शव का अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद दूसरे शव को पुलिस गांव लेकर पहुंची।

लिव–इन शादी और तलाक के नियमों में सरकार का बड़ा बदलाव

7 साल तक की हो सकती है जेल

चमोली ,उत्तराखंड सरकार ने राज्य में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड में अहम संशोधन किया है। यह कदम पिछले एक साल के अनुभवों और लागू कानून में सामने आई चुनौतियों के आधार पर उठाया गया है। संशोधन को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह की मंजूरी मिल चुकी है। नए अध्यादेश के बाद शादी और लिव–इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों में सजा के प्रावधान पहले से कहीं अधिक कड़े हो गए हैं।

जबरदस्ती या धोखे से रिश्ता बनाने पर सात साल की जेल

यदि कोई व्यक्ति जबरदस्ती, दबाव या धोखे के ज़रिए शादी या लिव–इन रिलेशनशिप में शामिल होता है, तो उसे सात साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करता है या लिव–इन रिलेशनशिप में रहता है, तो उस पर भी समान सजा लागू होगी।

लिव–इन रिलेशनशिप में भी सख्ती

कानून अब स्पष्ट करता है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी लिव–इन रिलेशनशिप में है और फिर किसी अन्य के साथ लिव–इन रिलेशनशिप में शामिल होता है, तो इसे अपराध माना जाएगा और सात साल तक की जेल हो सकती है। वहीं, बालिग का नाबालिग के साथ लिव–इन रिलेशनशिप करना छह महीने तक की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने के दायरे में आएगा।

बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को मिला ग्रैमी अवॉर्ड, दुनिया भर में बना चर्चा का विषय

नई दिल्ली ,बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने प्रेरणादायक और अर्थपूर्ण जीवन में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि जोड़ ली है। 90 साल की उम्र में उन्होंने वह कर दिखाया है, जो शायद ही किसी ने सोचा हो। 68वें ग्रैमी अवॉर्ड्स में दलाई लामा ने अपना पहला ग्रैमी जीतकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। यह सम्मान उन्हें उनके खास ऑडियो प्रोजेक्ट मेडिटेशन: द रिफ्लेक्शन्स ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा के लिए मिला है। इस उपलब्धि के बाद दलाई लामा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने लिखा, मैं यह सम्मान कृतज्ञता और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। मैं इसे व्यक्तिगत चीज के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे हमारी साझा सार्वभौमिक जिम्मेदारी की पहचान मानता हूं। मेरा सच में मानना है कि शांति, करुणा, हमारे पर्यावरण की देखभाल, और मानवता की एकता की समझ सभी आठ अरब इंसानों की सामूहिक भलाई के लिए जरूरी हैं। मैं आभारी हूं कि यह ग्रैमी सम्मान इन संदेशों को और ज्यादा लोगों तक फैलाने में मदद कर सकता है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना का निधन, अलवर में ली अंतिम सांस

अलवर ,भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, दो बार विधायक और वसुंधरा राजे सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हेम सिंह भड़ाना का सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे अलवर में उनके निवास पर 60 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन की खबर से अलवर और खैरथल–तिजारा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वे लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और कुछ दिन पहले उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, जिसके बाद वे काफी समय तक गुड़गांव के अस्पताल में भर्ती रहे।

सोमवार सुबह करीब 6:30 बजे अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। परिजन उन्हें गंभीर हालत में अलवर के टेल्को चौराहे स्थित हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। हॉस्पिटल के संचालक डॉ. हरीश गुप्ता ने बताया कि जब उन्हें इमरजेंसी में लाया गया, तब तक उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हेम सिंह भड़ाना अपने पीछे पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। वे अलवर शहर के वीर सावरकर नगर, खाटू श्याम मंदिर के पास रहते थे। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव भगेरी कला (किशनगढ़ बास विधानसभा क्षेत्र) में किया जाएगा, जो वर्तमान में खैरथल–तिजारा जिले में आता है। उनके निधन के चलते अलवर और खैरथल में आज भाजपा के सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हेम सिंह भड़ाना का जन्म 7 फरवरी 1966 को हुआ था।

उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से एलएलबी की पढ़ाई की थी। वे शुरू से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे। वर्ष 1991 से 1992 तक वे राजकीय कला एवं विधि महाविद्यालय, अलवर के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे।

सम्पादकीय

संवेदनहीन पुलिस तंत्र

उत्तराखंड को वैसे तो देवभूमि कहा जाता है लेकिन राज्य निर्माण के बाद से ही उत्तराखंड विभिन्न प्रकार के जगन ने अपराधों के लिए भी सुर्खियों में रहा है। राज्य की थोपी गई राजधानी देहरादून में तो कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से ही सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन इधर पिछले कुछ समय से आपराधिक घटनाओं का बेहद दुर्दांत चेहरा देखने को मिल रहा है। मात्र एक सप्ताह के अंदर जनपद देहरादून में तीन महिलाओं की हत्या की गई लेकिन जिस हत्या ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया वह देहरादून कोतवाली से चंद कदमों की दूरी पर भीड़ भरे मच्छी बाजार क्षेत्र में गठित हुई। यहां तीन साल की दोस्ती में दरार आने के बाद सिरफिरे युवक ने युवती को घर से बाहर बुलाकर उसकी गला रेत कर सड़क पर ही निर्मम हत्या कर दी। चंद मिनट में घटित हुई इस लोमहर्षक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया। इससे पहले की युवती को अस्पताल पहुंचाया जाता उसने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया लेकिन इससे पहले उसकी सनक ने एक पूरे परिवार के आगे उम्र भर की सिसकियां छोड़ दी। इस पूरे प्रकरण में देहरादून कोतवाली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं जिसने युवती द्वारा टीम दिन पहले की गई शिकायत को नजरअंदाज किया जिसके परिणाम स्वरूप युवती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस पूरे मामले में जांच से जुड़े तथ्य अभी आने बाकी है लेकिन इस बात से पुलिस बच नहीं सकती कि आखिर एक पीड़ति लड़की की शिकायत के बावजूद उसकी सुरक्षा को लेकर निष्क्रियता क्यों बरती गई? निश्चित तौर पर जिन पुलिसकर्मियों ने लड़की की शिकायत को अनदेखा किया उन पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। शिकायत किए जाने के बावजूद भी कुछ पुलिसकर्मियों की इस संवेदनहीनता के कारण ही लड़कियां पुलिस तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाती हैं और जो साहस दिखाकर शिकायत करती हैं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। ऐसे पुलिसकर्मियों के कारण प्रदेश में अपराधिक प्रवृति वाले व्यक्तियों का साहस बढ़ सकता है। इस प्रकार के कर्मी न केवल संवेदनहीन हैं बल्कि इस अपराध में भागीदार भी हैं। ऐसी घटनाओं का समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इससे लोगों के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ती है और सामाजिक संतुलन कमजोर होता है। यह जरूरी है कि समाज मिलकर ऐसी घटनाओं की निंदा करे और अपने आस–पास जागरूकता बढ़ाए। जब ऐसी जघन्य वारदातें होती हैं, तो जनता सिर्फ 'कागजी कार्रवाई' या 'फॉर्मेलिटी' नहीं, बल्कि ठोस परिणाम चाहती है। भविष्य में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को ऐसे उपायों पर काम करना चाहिए जिससे समाज में सुरक्षा का भाव मजबूत हो सके और लोगों का कानून व्यवस्था पर भरोसा बढ़े। समाज में एक तरफ तो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ हिम्मत जुटाकर शिकायत करने वाली लड़कियों की पीड़ा को किस प्रकार से पुलिस तंत्र अनदेखा करता है यह घटना इस कर्तव्यहीनता की एक जीती जगती मिसाल है।

भाजपा की राजनीतिक योजना क्या है?

अजीत द्विवेदी

तो समझना चाहिए कि उसे उसी तरह से प्लान किया गया है। यानी उसकी योजना ऐसी बनी है कि वह अनप्लांड लगे। यह बात अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कही थी। पूरी दुनिया की राजनीति पर यह बात समान रूप से लागू होती है। तभी प्रयागराज में शंकराचार्य को लेकर जो कुछ हो रहा है और उसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी का जो नया नियम लाया गया हैं उसे अनायास हुए नहीं मानना चाहिए। सरकार ने किसी योजना के तहत यूजीसी के नए नियम लागू किए हैं। उसने सामान्य वर्ग को अलग थलग करने और उसे उत्पीड़क साबित करने का जो नियम बनाया है वह संयोग नहीं है, बल्कि किसी प्रयोग का हिस्सा है।

इस समय पूरे देश में यूजीसी की ओर से लाए गए समानता के नए नियम पर विवाद हो रहा है। यूजीपी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीच्यूट रेगुलेशन 2026 के नाम से नए नियम जारी किए हैं। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव खत्म करना बताया गया है। इस तरह का एक नियम 2012 में बना था, जो पहले से उपलब्ध था। उसमें कुछ बदलाव करके उसे नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। 2012 के नियम में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी को उत्पीड़न से बचाने का प्रावधान किया गया था। अब उसमें अन्य पिछड़ी जातियों यानी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है। साथ ही महिलाएं और दिव्यांगजनों को भी शामिल किया गया है। महिलाओं और दिव्यांगों में हर वर्ग के छात्र शामिल होंगे।

इसका मतलब है कि सामान्य वर्ग के एक छोटे से समूह को पहले से ही अत्याचारी या उत्पीड़क मान कर बाकी लोगों को उससे बचाने का प्रावधान किया गया है। 2012 के कानून में भेदभाव या उत्पीड़न की फर्जी शिकायत करने पर कार्रवाई का प्रावधान था, जिसे नए नियमों में हटा दिया गया है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग अगर चाहें तो किसी भी सामान्य वर्ग के छात्र के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और शिकायत गलत पाए जाने पर उनके खिलाफ किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं हो सकती है। हर संस्थान में इक्विटी कमेटी और इक्विटी स्क्वॉयड बनाने का प्रावधान किया गया है, जिसमें बदलाव करके यह नियम बनाया गया है कि इसमें सामान्य वर्ग के किसी व्यक्ति को रखना अनिवार्य नहीं होगा।

सोचें, क्या इससे भी ज्यादा भेदभाव या असमानता की कोई व्यवस्था हो सकती है? इसमें एक समूह को पहले से अपराधी मान कर उसे सजा के योग्य ठहरा दिया गया है। यह सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला नियम है, जो कानून विरूद्ध है और संविधान विरूद्ध है।

यह प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के भी विरूद्ध है। भारत सरकार ने जब अंग्रेजों के जमाने की भारतीय दंड संहिता समाप्त की और उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता लागू की तो कहा कि अंग्रेजों ने दंड का प्रावधान किया था लेकिन अब सरकार न्याय की व्यवस्था ले आई है।

क्या यही न्याय की व्यवस्था है कि आप एक समूह को पहले से अपराधी मान लेंगे? सवाल है कि आरोप लगाए जाने और दोष सिद्ध होने से पहले किसी को अपराधी कैसे माना जा सकता है? भारत में न्याय की व्यवस्था महर्षि याज्ञवल्क्य के समय बनी, जिसमें वाचस्पति ने नव्य न्याय की धारणा जोड़ी। इसके मुताबिक दोष सिद्धि से पहले किसी को अपराधी नहीं माना जा सकता है।

संविधान का अनुच्छेद 14 और 15 कानून के समक्ष सबकी समानता और धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर किसी किस्म के भेदभाव को निरस्त करता है। लेकिन यहां भारत सरकार ने जाति के आधार पर एक समूह को पहले ही अपराधी मान लिया है। किसी सभ्य समाज में ऐसी व्यवस्था की कल्पना भी कैसे की जा सकती है?

इसी तरह का एक बिल मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार भी ले आई थी। कम्युनल वायलेंस बिल की मूल अवधारणा हिंदू को दंगाई मानने की थी। ऐसा कानून बन रहा था, जिसके मुताबिक कही भी दंगा होगा तो हिंदू को दोषी माना जाएगा। ठीक उसी तरह का नियम सरकार ले आई है, जिसके मुताबिक किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर भेदभाव होता है या उत्पीड़न की घटना होती है तो सामान्य वर्ग के छात्र या शिक्षक को उसका दोषी माना जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी, महिला और दिव्यांग कभी भी आरोपी या दोषी नहीं बनाए जाएंगे।

अब जरा इसके व्यावहारिक पक्ष की कल्पना करें। किसी भी शिक्षण संस्थान में जाने वाले सामान्य वर्ग के छात्र के ऊपर कितना मानसिक दबाव होगा। वह हर समय इस आशंका में रहेगा कि उपरोक्त पांच समूहों का कोई छात्र उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है और उसका करियर समाप्त कर सकता है। क्या सरकार कथित ऐतिहासिक गलतियों को दुरुस्त करने के लिए रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा से दूर करना चाहती है?

सरकार ने यह काम ऐसे समय में किया है, जब सामाजिक स्तर पर असमानता कम हो रही है, समाज ज्यादा समरस बन रहा है और सत्तारूढ़ दल खुद ही व्यापक हिंदू एकता के लिए काम कर रहा है। दूसरी ओर आर्थिक स्तर पर असमानता बढ़ रही है। सरकार का यह नियम विभिन्न जातियों और समाजों के बीच वैमनस्य और भेदभाव बनाने वाला प्रतीत होता है।

अगर इसके राजनीतिक पहलुओं को देखें तो क्या भारतीय जनता पार्टी और उसकी केंद्र सरकार को लग रहा है कि वह सामान्य वर्ग को अलग थलग करके या उसके प्रति द्वेष दिखा कर एससी, एसटी और ओबीसी के बड़े जातीय समूह को अपने साथ करे लेगी और इससे उसे चुनावी जीत का स्थायी फॉर्मूला मिल जाएगा? क्या वह कांग्रेस और प्रादेशिक पार्टियों की बहुजन राजनीति के जवाब के तौर पर यह नियम लेकर आई है?

ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि भाजपा के नेता अर्थव्यस्था, कूटनीति, प्रौद्योगिकी आदि समझें न समझें राजनीति बखूबी समझते हैं। उनके पता होता है कि किस बात से चुनावी नुकसान होगा और किस बात से फायदा होगा। तभी हैरानी हो रही है कि राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाला इतना बड़ा कदम इस सरकार ने कैसे उठाया।

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश के अल्पसंख्यकों को पहले ही अपने से अलग कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खुल कर 80 और 20 की लड़ाई बताई जाती है। लेकिन यह विभाजन राष्ट्रीय स्तर पर भी है। भाजपा ने 20 फीसदी अल्पसंख्यकों को अपने से अलग मान लिया है। उसे 80 फीसदी हिंदुओं की राजनीति करनी है। अब क्या वह इस 80 फीसदी के समूह को और छोटा करने की जोखिम ले सकती है? क्या इसमें से 15 फीसदी सामान्य वर्ग बाहर हो जाए तो भाजपा 65 फीसदी के वोट की राजनीति करके चुनाव जीत सकती है? ध्यान रहे सामाजिक स्तर पर एससी और एसटी का टकराव ओबीसी के साथ ज्यादा है।

एससी, एसटी उत्पीड़न कानून के तहत 80 से 90 फीसदी मामलों में आरोपी पिछड़ी जातियों के हैं। इस कानून के दुरुपयोग के अनगिनत मामले सामने आ चुके हैं और अदालतों ने इस पर अनेक बार टिप्पणियां की हैं। लेकिन शिक्षण संस्थान में ओबीसी को भी एससी और एसटी के साथ ही उत्पीड़न के शिकार वर्ग में शामिल किया जा रहा है। क्या इससे तीनों समूहों के बीच समाज में भी समरसता स्थापित हो जाएगी? इसमें संदेह है लेकिन इससे एससी, एसटी व ओबीसी के साथ सामान्य वर्ग के संबंधों में तनाव जरूर बढ़ जाएगा। क्या सरकार यह तनाव बढ़ाना चाहती है?

अगर राज्यवार देखेंगे तो भाजपा को राजनीतिक नुकसान की संभावना और ज्यादा दिखेगी। मिसाल के तौर पर झारखंड में मुस्लिम, ईसाई और आदिवासी भाजपा के खिलाफ हैं। अगर सामान्य वर्ग भी खिलाफ हुआ तो भाजपा के पास क्या बचेगा? उत्तर प्रदेश में 80 और 20 की लड़ाई है। 80 में से 10 फीसदी यादव को पहले ही भाजपा ने अलग कर दिया है। अगर बचे हुए 70 फीसदी में से 20 से 25 फीसदी सामान्य वर्ग के लोग अलग हुए तो भाजपा के पास क्या बचेगा राजनीति करने को?

भाजपा के नेता इतने नासमझ तो नहीं हैं कि वे यह मानने लगें कि शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी के साथ ओबीसी को भी शोषित वर्ग में शामिल कर देने से उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव भाजपा को वोट देने लगेंगे। दो तीन राज्यों के उदाहरण का विस्तार पूरे देश में किया जा सकता है। सो, कुल मिला कर यूजीसी का यह नियम सामाजिक विद्वेष बढ़ाने वाला और समानता की भावना के विपरीत तो है ही साथ ही भाजपा को बड़ा राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला भी हो सकता है। कहीं ऐसा न हो कि चौबे जी छब्बे जी बनने चलें और दुबे जी बन कर रह जाएं।

भारत और ईयू में मुक्त व्यापार संधि

डॉ. सुधीर सक्सेना

लगभग दो दशक की कवायद के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के मध्य मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो गए। इस संधि के अमल में आने में यद्यपि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अमेरिका के टैरिफ युद्ध के मटमैले साये में यूरोपीय देशों के लिए भारत के विशाल बाज़ार के दरवाजे खुल गए हैं और कुछ ही बरसों में भारतीय बाज़ार यूरोपीय साजो–सामान से पट जाएंगे। इसके फलस्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं को फ्रेंच वाइन समेत तरह–तरह की शराब और कारों के विकल्प सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगे। भारतीय महिलाएँ इस बात पर इतराएँगी कि अब उन्हें यूरोपीय सौंदर्य प्रसाधन और परिधान बेहतर गुणवत्ता के साथ कम कीमतों पर मिल सकेंगे।

गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य एफटीए के लिए वार्ता की शुरुआत डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्वकाल में वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 1992 में मास्त्रिख्त संधि के बाद अगले ही वर्ष रोम में सात देशों की मौजूदगी में ईयू अस्तित्व में आया था। वर्ष 2009 में लिस्बन समझौते से इसे गति और विस्तार मिला। आज यूरोप–महाद्वीप के 27 देश इसके सदस्य हैं। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसका ध्येय–वाक्य है–'अनेकता में एकताइ। इसकी मुद्रा यूरो है, अपना राष्ट्रगान है और वैश्विक साख है। पाबंदियों और टैरिफ के अनिश्चित और नाजुक दौर में ईयू की महत्ता बढ़ गई है। इस बीच एक बड़ी घटना यह भी हुई कि यूके वर्ष 2020 में ईयू से बाहर हो गया, लिहाज़ा इस दूरगामी महत्व की संधि का लाभ उसे नहीं मिलेगा।ईयू की अध्यक्ष उर्सुला फ़ॉन डेर लेयेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए को भारत और यूरोप के मध्य कारोबार के लिहाज़ से 'मील का पत्थरइ माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दंभ और धमकियों के दौर में इस संधि को यूरोपीय देशों की उद्योग–धंधों के लिए 'बूस्टर डोज़इ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का आभासी उद्घाटन करते हुए कहा कि यह संधि 'सभी सौदों की जननीइ है। उनका कहना था कि यह डील भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को फायदा पहुँचाएगी। उन्होंने कहा कि यह करार भारत की उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करेगा और सर्विस सेक्टर को नया संबल देगा।

इस महत्वपूर्ण संधि के तत्काल लागू न होने का कारण यह है कि पहले ईयू के सदस्य देशों की भाषाओं–जैसे फ्रेंच, जर्मन, इतालवी आदि–में इसका कानूनी दस्तावेज प्रकाशित होगा और फिर सभी धाराओं की सदस्य देशों में 'लीगल स्क्रबिंगइ होगी। तत्पश्चात यूरोपीय परिषद की औपचारिक मंजूरी और यूरोपीय संसद की सहमति आवश्यक है। इसके बाद भारतीय संसद की पुष्टि के उपरांत यह संधि लागू होगी। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसके इस वर्ष के भीतर अमल में आने की उम्मीद की जा सकती है।अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ पुष्परंजन मानते हैं कि इस बूस्टर डोज़ से ईयू के सदस्य देशों को बहुविध लाभ होगा। उनका मानना है कि भारत ने किसी भी व्यापारिक सहयोग को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग पहले कभी नहीं दी। उनकी बात की पुष्टि यूरोपीय कमीशन के आधिकारिक बयान से होती है। इससे यूरोपीय देशों के माल की भारतीय बाज़ारों में पहुँच और खपत आसान हो जाएगी। कमीशन ने एक चार्ट के ज़रिये वर्ष 2024 के आकलन के आधार पर बताया है कि मशीनरी और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर उसे 16.3 बिलियन यूरो टैरिफ देने पड़े थे। अब इसके शून्य होने से बड़ा लाभ होगा। इसी तरह विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर प्रदत्त 11 प्रतिशत के मान से 6.4 अरब यूरो की बचत होगी।कल्पना कीजिए कि मशीनरी पर 44 प्रतिशत, रसायनों पर 22 प्रतिशत और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत टैरिफ यदि शून्य हो जाता है, तो यूरोपीय कंपनियों को कितना मुनाफा होगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर 27.5 प्रतिशत टैरिफ यदि हट जाए तो करीब तीन बिलियन यूरो बचेंगे। प्लास्टिक पर जीरो टैरिफ से दो बिलियन से अधिक की बचत होगी। यदि लोहे और इस्पात पर 22 प्रतिशत टैरिफ निरस्त होता है तो डेढ़ अरब यूरो से अधिक की बचत होगी। संधि से पहले पारस्परिक कारोबार से आठ लाख नौकरियों का समर्थन मिलता रहा है, अब इसमें भारी बढ़ोत्तरी होगी।इस संधि से यूरोपीय किसानों की बाँछें खिलना स्वाभाविक है, क्योंकि एग्रो–फूड पर 36 प्रतिशत शुल्क में कमी से उन्हें बड़ा बाज़ार मिलेगा। संधि से मदिरा प्रेमी भी खुश होंगे, क्योंकि वाइन पर 150 प्रतिशत टैक्स घटकर 30 प्रतिशत पर आ जाएगा। बीयर पर टैक्स 110 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगा। लगभग 350 तरह के फलों, फलों के रस, चॉकलेट, ब्रेड, पेस्ट्री, सॉसेज और मांसाहारी व्यंजनों पर भी टैरिफ घटने से ये भारतीयों को सस्ते में मिलेंगे।फिलहाल यूरोपीय संघ के देशों में इस संधि के नफे–नुकसान पर बहस जारी है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला का कहना है कि इस संधि से लाखों नौकरियाँ सृजित होंगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा कहते हैं कि हम दो अरब लोगों के लिए बाज़ार बना रहे हैं।अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या भारतीय कंपनियाँ और किसान आयातित चीज़ों की बाढ़ के बीच यूरोपीय मानकों और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि भारत के 140 करोड़ और यूरोप के 45 करोड़ लोगों के लिए एफटीए कितना बड़ा अवसर लेकर आता है? पुष्परंजन का यह सवाल वाजिब है कि यह भी देखना होगा कि इस संधि का भारत–अमेरिका और भारत–चीन संबंधों व व्यापार पर क्या असर पड़ता है?

श्री विष्णु की अगली फिल्म का शीर्षक विष्णु विन्यासम फरवरी में होगी रिलीज

मनोरंजन के बादशाह श्री विष्णु, जो अपनी अनूठी पसंद और दमदार मनोरंजन के लिए जाने जाते हैं, तेलुगु सिनेमा में अपना अलग ही मुकाम बनाए हुए हैं। फिलहाल वे श्री सुब्रह्मण्येश्वर सिनेमाज बैनर के तहत बन रही एक और अनूठी मनोरंजक फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन पहली बार निर्देशक बने यदुनाथ मारुति राव कर रहे हैं और इसका निर्माण सुमंत नायडू जी कर रहे हैं। यह बैनर कंपनी की तीसरी फिल्म है। हेमा और शालिनी इस प्रोजेक्ट की मुख्य भूमिका में हैं, जबकि साई कृष्णा बोब्बा और रामाचारी एम सह–निर्माता के रूप में जुड़े हैं। फिल्म निर्माताओं ने आज एक एनिमेशन वीडियो के जरिए फिल्म के शीर्षक की घोषणा की, जिसमें फिल्म की पृष्ठभूमि भी दिखाई गई है।

फिल्म निर्माताओं ने आज एक स्टाइलिश एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से फिल्म के शीर्षक का अनावरण किया, जिसमें इसके बैकग्राउंड की झलक भी मिलती है। शहरी परिवेश में फिल्माए गए इस वीडियो में श्री विष्णु को एक खास पीले रंग की मोटरसाइकिल पर शहर में तेजी से घूमते हुए दिखाया गया है, जो तुरंत ही फिल्म का मिजाज तय कर देता है। फिल्म का नाम दिलचस्प ढंग से विष्णु विन्यासम रखा गया है, जो अभिनेता के विलक्षण पर्दे के व्यक्तित्व को बखूबी दर्शाता है। उनकी अनोखी हरकतों और खास हास्य को उजागर करते हुए, शीर्षक का अनावरण आकर्षक टैगलाइन, नो ब्रेक्स – जस्ट लाफ्स के साथ किया गया है।

पाकिस्तान पर बैन का खतरा... भारत के खिलाफ मैच से हटने पर पूर्व खिलाड़ी ने बोली बड़ी बात

नईदिल्ली, भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच से पाकिस्तान के हटने पर पूर्व पाकिस्तानी खिलाड़ी राशिद लतीफ ने प्रतिक्रिया दी है. उनका मानना है कि पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की संभावना कुछ समय से बनी हुई है, लेकिन उनका ये कड़ा रुख आखिरकार सभी हितधारकों को बातचीत की मेज पर वापस ला सकता है.

राशिद लतीफ के बयान तब सामने आया जब पाकिस्तन की सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की सरकार आईसीसी वर्ल्ड टी20 2026 में भाग लेने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मंजूरी देती है, हालांकि, पाकिस्तान क्रिकेट टीम 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ निर्धारित मैच में मैदान पर नही उतरेगी. पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने कहा, पाकिस्तान ने आखिरकार बड़ा और कड़ा कदम उठाया है, इसकी वजह से उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, और उन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए. हम पिछले हफ्ते से इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा नतीजा संभव है. अब बातचीत शुरू हो सकती है, खासकर ब्रॉडकास्टर्स के शामिल होने के साथ, क्योंकि इस मैच में बहुत सारा पैसा दांव पर लगा है.

ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026: कालीस अल्काराज ने जोकोविच को हराकर जीता पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन

नईदिल्ली, कालीस अल्काराज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के टाइटल मुकाबले में जीत हासिल की, मेलबर्न पार्क में खिताबी मुकाबले में 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच को हराकर इतिहास रच दिया. वो 22 साल की उम्र में चारो ग्रैंड स्लैम (ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन) जीतने वाले सबसे छोटे खिलाड़ी बन गए हैं.

फाइनल मैच में 22 वर्षीय अल्काराज को 38 वर्षीय जोकोविच ने कड़ी टक्कर दी. अल्काराज पहला सेट 6–2 से हार गए क्योंकि इस सेट में उनकी सर्विस दो बार ब्रेक हुई. हालांकि, उन्होंने अगले तीन सेट 6–2, 6–4, और 7–5 से जीतकर अपना पहला खिताब जीता लिया.

यह युवाओं और अनुभव के बीच मुकाबला था, जिसमें टेनिस की दुनिया के उभरते सितारे 22 साल के खिलाड़ी का सामना एक अनुभवी खिलाड़ी से था, जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. सर्बियाई खिलाड़ी ने मैच की शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन आखिरकार दोनों की फिटनेस का अंतर दिखने लगा, और जोकोविच ने अपने विरोधी को चकमा देने के लिए ड्रॉप शॉट्स पर ध्यान देना बेहतर समझा. अल्काराज का कोर्ट कवरेज शानदार था, और इसने उन्हें लगातार तीन सेट जीतकर जीत हासिल करने में मदद की.

दृश्यम 3 रिलीज डेट का एलान, 2 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी मोहनलाल की फिल्म

मोहनलाल की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी है. रिलीज डेट को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियली अनाउंस किया. यह डेट काफी खास है, क्योंकि यह अजय देवगन से जुड़ा हुआ है. इस अनाउंसमेंट से फ्रेंचाइजी के फैंस में काफी दिलचस्पी पैदा हुई है, जो जॉर्जकुट्टी की कहानी के आगे बढ़ने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे. दिलचस्प बात यह है कि मोहनलाल की दृश्यम 3 हिंदी रीमेक से छह महीने पहले रिलीज होगी. इस अनाउंसमेंट के साथ मोहनलाल ने एक वीडियो पोस्ट भी किया गया, जिसमें फैंस को कहानी के बारे में कोई भी डिटेल बताए बिना फिल्म की एक झलक दिखाई गई. फिल्म की रिलीज के बारे में जानकारी देते हुए मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने एक्स हैंडल पर अनाउंसमेंट टीजर शेयर किया है और कैप्शन में लिखा है, साल बीत गए, लेकिन अतीत नहीं बीता, दृश्यम3 वर्ल्डवाइड रिलीज 2 अप्रैल, 2026.

मोना सिंह महिलाओं को एक्सपायरी डेट मिलने पर बोलीं– मुझे उम्र की परवाह नहीं

जस्सी जैसी कोई नही टीवी शो से लोकप्रिय हुईं मोना सिंह इन दिनों धड़ाधड़ फिल्में और सीरीज कर रही हैं। हाल ही में उन्हें बॉर्डर 2 और हैप्पी पटेल जैसी फिल्मों में देखा गया। अब उनकी सीरीज कोहरा 2 नेटफ्लिक्स पर आने के लिए तैयार है। प्रमोशन के दौरान 40 वर्षीय मोना ने पर्दे पर 50 और 60 साल की उम्र के किरदार पर बात की। साथ ही सिनेमा जगत में महिलाओं को एक्सपायरी डेट दिए जाने पर प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री बोली, मुझे पर्दे पर अपनी उम्र की परवाह नहीं। सच में नही, क्योंकि मैं बहुत आत्मविश्वासी हूं और मैं जानती हूं कि मैं कौन हूं। मुझे कुछ साबित करने की जरूरत नही है, इसीलिए मैं जोखिम लेती रहती हूं। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, आप पर्दे पर इतनी उम्रदराज क्यों दिखती हैं? मैं कहती हूं कि इससे कोई फर्क नही पड़ता। ये वो किरदार है जिसे मैं निभा रही हूं। ये मुझे उत्साहित करता है।

टी20 वर्ल्ड कप 2026: भारत के खिलाफ मैच बॉयकॉट करने पर आईसीसी का आया बड़ा बयान, पाकिस्तान का होगा बड़ा नुकसान

नईदिल्ली,। टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश का ड्रामा खत्म होने के बाद दूसरा ड्रामा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की सरकार ने रविवार को अपनी नेशनल क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप में भाग लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन बिना कोई कारण बताए 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलने से मना कर दिया.पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसला के कई कारण बता रहा है, जिसमें मुख्य कारण बांग्लादेश को लेकर आईसीसी का पक्षपातपूर्ण फैसला बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी सरकार इस मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाना चाहती थी, इसी विरोध में पाकिस्तानी टीम से 15 फरवरी को भारत के साथ मैच न खेलने को कहा गया है.पाकिस्तान के इस फैसले पर अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ ग्रुप ए मैच का बहिष्कार करने का फैसला ग्लोबल क्रिकेट की अखंडता को कमजोर करता है. और इसकी वजह से पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा नुकसान हो सकता है.

आईसीसी ने यह भी कहा कि वह इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से आधिकारिक जानकारी का इंतजार कर रहा है. आईसीसी ने अपने बयान में कहा, आईसीसी टूर्नामेंट खेल की अखंडता, प्रतिस्पर्धा, निरंतरता और निष्पक्षता पर आधारित होते हैं, और चुनिंदा रूप से हिस्सा लेना प्रतियोगिताओं की भावना और पवित्रता को कमजोर करता है. हालांकि आईसीसी राष्ट्रीय नीति के मामलों में सरकार की भूमिका का सम्मान करता है,

एक नजर

एलयूसीसी पीड़ितों ने उठाई कंपनी के फरार संचालन की गिरफ्तारी की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : द लोनी अरबन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोआपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) पीड़ितों ने कंपनी के फरार संचालकों को अभी तक गिरफ्तार न किए जाने पर आक्रोश जताया।

पीड़ितों ने तहसील में धरना दिया। कहा कि सभी पीड़ित विगत 209 दिनों से तहसील परिसर में धरना दे रहे है। लेकिन, शासन-प्रशासन उनके आंदोलन की अनदेखी कर रही है, जिससे पीड़ितों में शासन-प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है।

कहा कि भले ही प्रदेश सरकार मामले की सीबीआई जांच की बात कर रही है। लेकिन, अभी तक कंपनी के मुख्य फरार संचालकों को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

कहा कि कंपनी के फरार संचालकों ने ही कंपनी में धन दोगुना करवाने का लालच दिया था, जिससे बड़ी संख्या में निवेशकों ने कंपनी में धन जमा करवाया। लेकिन, जब कंपनी में करोड़ों रूपया जमा हो गया तो कंपनी के संचालक अपने कार्यालयों में ताला लगाकर फरार हो गए। पीड़ितों ने शासन-प्रशासन से फरार संचालकों को गिरफ्तार कर डूबी रकम वापस दिलवाने की मांग की है। इस मौके पर वीरेंद्र सिंह रावत, सुनीता रावत, सरोज गौड़, रीता, हरेंद्र रावत मौजूद रहे।

डॉ. बमराड़ा को मिला शोध पत्र लेखन में प्रथम स्थान

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जनवरी में एआई के सुरक्षित उपयोग विषय पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौंरखाल के शिक्षक डॉ. अतुल बमराड़ा ने तकनीकी शोध पत्र लेखन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया व विद्यालय की टीम ने नाट्यकला प्रतियोगिता के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक में शीर्ष स्थान हासिल किया।

डॉ. अतुल बमराड़ा ने बताया कि उन्होंने अपने शोध पत्र में एआई के तकनीकी उपयोग, उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियों और डिजिटल साक्षरता के महत्व को प्रस्तुत किया। वहीं, विद्यालय की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एआई के सुरक्षित उपयोग, साइबर सुरक्षा और डिजिटल सतर्कता से जुड़े संदेश को रचनात्मक और सरल तरीके से आमजन तक पहुंचाया। डॉ. अतुल बमराड़ा और राप्रावि चौंरखाल की टीम को मंत्रालय की ओर से प्रमाणपत्र और पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका नंदा रावत ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इस सम्मान से न केवल विद्यालय बल्कि पूरे जिले और राज्य में सरकारी शिक्षा संस्थानों की प्रतिष्ठा बढ़ी है।

डीसीबी के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत को दी श्रद्धांजलि

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जिला सहकारी बैंक (डीसीबी) के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत (कुट्टी भाई) का आकस्मिक निधन हो गया है। उनके असामयिक निधन पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, सांसद अनिल बलूनी, विधायक राजकुमार पोरी व जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने गहरा दुःख जताया है।

जिला पंचायत सदस्य कलुंण भरत रावत ने बताया कि नरेंद्र सिंह रावत पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और उनका उपचार दिल्ली से किया जा रहा है। बीते रविवार देर शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। सोमवार को तिरपालीसैंण स्थित पैतृक घाट में उनकी अंत्येष्टि हुई। वे करीब 56 साल के थे। वे अपने पीछे पत्नी/पूर्व प्रमुख मंजू रावत व दो बेटों को छोड़ गए हैं। वहीं नरेंद्र सिंह रावत के निधन पर भाजपा जिला कार्यालय में शोक सभा आयोजित कर उन्हें श्रद्धांजली दी गई। इस मौके पर जिला महामंत्री गणेश भट्ट, महिपाल नेगी आदि मौजूद रहे।

लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग निर्माण को निकाली आक्रोश रैली

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर सोमवार को शहर में आक्रोश रैली निकाली गई। लोगों ने सरकार से जल्द से जल्द मार्ग निर्माण की मांग उठाई। कहा कि लगातार आंदोलन के बाद भी क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है।

सोमवार को बड़ी संख्या में लोग देवी मंदिर के समीप पहुंचे। यहां से लोगों ने लालबत्ती चौराहा, झंडाचौक होते हुए तहसील परिसर तक आक्रोश रैली निकाली। इसके उपरांत लोगों ने प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। वक्ताओं ने कहा कि स्थानीय जनता पिछले लंबे समय से मार्ग निर्माण की मांग उठा रही है। बावजूद उनकी अनदेखी की जा रही है। कहा कि राज्य वन्य जीव संरक्षण बोर्ड व राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण बोर्ड ने हरी झंडी मिलने के बाद भी मोटर मार्ग निर्माण में आ रही बाधाओं को दूर नहीं किया जा रहा है। कहा कि क्षेत्र की जनता के हितों को देखते हुए प्रदेश सरकार को न्यायालय में ठोस पैरवी कर बाधाओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि एलीवेटेड रोड की एक मात्र विकल्प है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को पहल करनी होगी। इस मौके पर मदन सिंह नेगी, राजेंद्र सिंह सौंद, प्रवीण थापा, उम्मेद सिंह, राम कंडवाल, डा. शक्तिशैल कपरवाण, मधूसूदन नेगी, देवेंद्र रावत, रमेश भंडारी, हेमा नेगी, प्रदीप नेगी, पुष्पा देवी, दीपा अधिकारी, राजाराम अण्थ्वाल, भारती देवी, प्रकाश रावत मौजूद रहे।

लालढांग-चिलरखाल वन मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर कोटद्वार के झंडाचौक में प्रदर्शन करते आंदोलनकारी

फाउंडेशन ने स्कूली बच्चों को बांटी स्वेटर

आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को स्वेटर वितरित करते संस्था के सदस्य

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नंबर चार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें जय सिद्धबली फाउंडेशन की ओर से स्कूली बच्चों को स्वेटर वितरित की गई।

आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को बेहतर शिक्षा से जोड़ने का भी संकल्प लिया गया। साथ ही फाउंडेशन ने विद्यार्थियों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कहा कि बच्चों को जीवन में लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना चाहिए। मेहनत करने वालों को जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कहा कि जय सिद्धबली फाउंडेशन की ओर से समय-समय पर बच्चों की मदद के लिए इस तरह का अभियान चलाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अन्य संस्थाओं को भी आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए। इस मौके पर हरीश खर्कवाल, अमित भारद्वाज, मनोज कुडलिया, पंकज भाटिया, सुरेश शर्मा, रानी नेगी, विकास अग्रवाल, सुनीता ढौंडियाल आदि मौजूद रहे।

मारपीट के चार आरोपी दोष मुक्त

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी शहजाद ए वाहिद की अदालत ने मारपीट करने वाले चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। पीड़ित ने अदालत में विरोधाभाषी घटनाक्रम बनाएं। अभियोजन पक्ष अदालत में आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। एपीओ वर्षा ने बताया कि 10 मार्च 2025 को शोभा सिंह कार से अपने मित्र के साथ सीकू गांव में एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि शाम में मांडाखाल के समीप मनोज रावत, राहुल, दीपक व दिग्विजय ने कार से पहले रास्ता रोका और उनके मित्र को भगा दिया। इसके बाद उनके साथ गाली गलौज व मारपीट की, जिससे उनके हाथ-पैरों में चोटें आई। बाद में आरोपियों ने उन्हें फोन कर जान से मारने की धमकियां दीं। मामले में उन्होंने 19 मार्च 2025 को कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और मामला एक जुलाई को अदालत पहुंचा। एक अगस्त को आरोपियों को जमानत मिल गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता जयदर्शन सिंह बिष्ट ने दलील दी कि पीड़ित ने एफआईआर विलंब से दर्ज की और विलंब को कोई ठोस कारण नहीं बताया। साथ ही पीड़ित ने मारपीट के बाद आई चोटों का भी मेडिकल नहीं करवाया। यहां तक कि पीड़ित शोभा सिंह ने अदालत को विरोधाभाषी घटनाक्रम बताए। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को सिद्ध करने में असफल रहा। जिस पर अदालत ने आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।

क्षत्रिय उत्थान संस्था ने किया यूजीसी का विरोध

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : उत्तराखंड क्षत्रिय उत्थान संस्था ने यूजीसी अधिनियम का विरोध किया है। कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करना चाहिए। इस अधिनियम से समाज में मतभेद होगा।

इस संबंध में संस्था ने प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार को सभी जातियों के लिए समान तरीके से कार्य करना चाहिए।

यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन पूर्ण रूप से असंवैधानिक व अस्पष्ट है, जो समाज में असमानता का भाव पैदा करेगा। कहा कि इस कानून के लागू होने से शिकायत करने का अधिकार मात्र कुछ वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह जाएगा। कहा कि भले ही एक जनहित याचिका का संज्ञान लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी हो, लेकिन इस कानून को वापस लेकर इसे निरस्त किया जाए। इस मौके पर भारत सिंह नेगी, बलवीर सिंह रावत, त्रिलोक सिंह, हरेंद्र सिंह, राजेंद्र बिष्ट मौजूद रहे।

कांग्रेस ने उठाई दीपक को सुरक्षा देने की मांग

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : गढ़वाल के प्रवेश द्वार कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने दीपक कुमार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग उठाई। कहा कि कुछ दिन पूर्व कोटद्वार शहर में पहुंचे कुछ लोगों ने उत्पात मचाया था। साथ ही दीपक के जिम में घुसने का भी प्रयास किया गया। कहा कि शहर में सौहार्द बना रहे इसके लिए पुलिस को गंभीरता से कार्य करना चाहिए।

सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारी कोटद्वार कोतवाली में पहुंचे। जहां उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह से वार्ता की। कांग्रेस नेत्री ज्योति रौतेला व जिलाध्यक्ष विकास नेगी ने कहा कि कुछ लोग शहर का संप्रदायिक माहौल खराब करने के लिए एक मुस्लिम समाज के युवक की दुकान में पहुंचे और दुकान के नाम को लेकर विवाद करने लगे। इसी दौरान मौके पर मौजूद दीपक ने इंसानियत का परिचय देते हुए बुजुर्ग दुकानदार का पक्ष लिया और उक्त लोगों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कहा कि शहर में भाई-चारे का संदेश देने वाले दीपक की सुरक्षा के लिए पुलिस को गंभीरता से कार्य करना चाहिए। कुछ दिन पूर्व देहरादून सहित अन्य शहरों से बड़ी संख्या में पहुंचे व्यक्तियों ने उनके ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया। बताया कि बड़ी संख्या में देहरादून व हरिद्वार से युवकों के शहर में पहुंचना भी पुलिस का फेलियर है। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह ने कहा कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है। इसके लिए पुलिस का अतिरिक्त फोर्स शहर में तैनात किया गया है। महौल खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिम के बाहर तैनात फोर्स

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी अपनी कमर कस ली है। मालवीय उद्यान स्थित दीपक के जिम के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। यही नहीं समय-समय पर पुलिस अधिकारी भी उक्त स्थान पर गश्त कर रहे हैं। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति से निपटने के लिए शहर में अतिरिक्त पुलिस फोर्स बुलवाया गया है। शहर के मुख्य चौराहों पर भी पुलिस की तैनात की गई है।

कोटद्वार कोतवाली में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह से वार्ता करते कांग्रेसी

पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : शहर में दुकान के नाम को लेकर हुए विवाद के बाद शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार शाम पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान आमजन से भी कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई।

26 जनवरी को पटेल मार्ग में एक दुकान के नाम को लेकर विवाद हो गया था। वीडियो इंटनेट पर वायरल होने के बाद लोगों ने उसपर अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारंभ किया। साथ ही अगले दिन बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद व बजरंगदल के सैकड़ों कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और मामले से जुड़े युवक के जिम की ओर बढ़ने लगे। मौके पर तैनात पुलिस ने मामले को शांत करवाया। इसके बाद भी सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर गहमा-गहमी बनी हुई है। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोमवार शाम कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के दौरान संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरती गई। इस दौरान आम नागरिकों से शांति, सौहार्द एवं सहयोग बनाए रखने की अपील की गई। पुलिस द्वारा यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि किसी भी प्रकार की अफवाह, अराजकता अथवा कानून-व्यवस्था भंग करने के प्रयासों को सख्ती से रोका जाएगा।

बदरीनाथ मार्ग पर पुलिस कर्मी फ्लैग मार्च निकालते हुए।

नाट्य प्रस्तुतियों ने मोहा दर्शकों का मन

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : कोट विकासखंड स्थित ब्रिगेडियर विद्याधर जुयाल संस्कृत विद्यालय, भुवनेश्वरी में पुरातन छात्र सम्मेलन एवं गुरु सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित गुरुसम्मान समारोह में पुराने छात्रों की ओर से शिक्षक नवीन जुयाल को स्मृति-चिह्न एवं सम्मानपत्र देकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

विद्यालय के पूर्व छात्र डॉ. नवीन ममगाईं ने बताया कि विद्यालय की स्थापना को लगभग 35 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। इस शिक्षण संस्था को इस मुकाम तक पहुंचाने में स्व. अनिल जुयाल, अनसूया प्रसाद सुंदरियाल एवं नवीन जुयाल समेत कई शिक्षकों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने गीत, नृत्य एवं नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधक राजेंद्र जुयाल, प्रधानाचार्य अनसूया प्रसाद सुंदरियाल, दुर्गा जुयाल, दीपक नवानी, पंकज ममगाईं आदि मौजूद रहे।

शहर में निकली संत शिरोमणि रविदास की भव्य झांकी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : संत शिरोमणि रविदास सेवा समिति की ओर से संत शिरोमणि रविदास की 649वीं जयंती पर शहर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा को देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी।

सोमवार शाम कैड़िया से निकाली गई शोभायात्रा में संत शिरोमणि रविदास की झांकी व संविधान की झांकी आकर्षक का केंद्र रही। यात्रा के दौरान युवाओं की ओर से हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। संत शिरोमणि रविदास सेवा समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रतिवर्ष रविदास जयंती पर शहर में शोभायात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा को लेकर बच्चों व महिलाओं में उत्साह बना हुआ था। कौड़िया से बाजार क्षेत्र के लिए निकली शोभायात्रा का लोगों ने जगह-जगह स्वागत भी किया। आयोजकों ने लोगों को संविधान के महत्व के बारे में बताया। कहा कि देश की सबसे बड़ी ताकत संविधान है। इसलिए हमें संविधान के बारे में जानकारी होनी अति आवश्यक है। इससे पूर्व एक फरवरी को कौड़िया में झंडा भी पहराया गया। साथ ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया।

कौड़िया क्षेत्र में निकाली गई शोभायात्रा में शामिल संत रविदास की झांकी

उत्तराखंड ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप में एवीएन ने जीते आठ स्वर्ण सहित 20 पदक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : भाबर के एवीएन पब्लिक स्कूल के छात्रों ने ताइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) की ओर से योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार में आयोजित उत्तराखंड ओपन स्टेट ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए आठ स्वर्ण, पांच रजत और सात कांस्य पदक अपने नाम किये। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालय, अभिभावकों एवं क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई।

विद्यालय के डायरेक्टर रजनीश शर्मा ने बताया कि टीएफआई कि ओर से योगस्थली खेल परिसर रोशनाबाद, हरिद्वार में एक दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट करते हुए देवांश काला, शौर्य कुमार, परिणीति मौर्य, अभिनव सिंह, माही रावत, समिक्षा कोटनाला, वंश रावत और नक्ष गुसाईं ने स्वर्ण, यश रावत, रुद्र कोटनाला, हिमानी बिष्ट, मनन गौर एवं अन्विक्षा कोटनाला ने रजत और प्रियांशु लखेड़ा, अंशिका राणा, एंजेल, शौर्य बूड़ाकोटी, निखिल रावत, संस्कृति, पिहू सिन्हा एवं अंशिका रावत ने कांस्य पदक जीता। विद्यालय की संचालिका अनुराधा नैथानी शर्मा ने छात्रों की इस सफलता का श्रेय कोच मुकेश सिंह और संदीप सैनी को दिया जिनके मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। विद्यालय प्रबंधन ने सभी विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू, 1.30 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जनपद पौड़ी में पशुपालन विभाग ने लंपी रोग की रोकथाम के लिए पशुओं का टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। जिले में कुल एक लाख 63 हजार पशुओं के सापेक्ष विभाग ने 1 लाख 30 हजार पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। साथ ही टीकाकरण के लिए विभाग ने 80 टीमें गठित की हैं जो घर-घर जाकर पशुओं का टीकाकरण कर रही हैं। सीवीओ डॉ. शर्मा ने बताया कि गाभिन (गर्भवती), छह माह से कम उम्र और बीमार पशुओं का टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने टीकाकरण अभियान को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। यह अभियान जनपद के 15 विकासखंडों की 1166 ग्राम पंचायतों और 7 नगरीय निकाय क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (सीवीओ) डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि लंपी रोग गाय और भैंसों में होने वाली एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो कैप्रिपॉक्स वायरस के कारण फैलती है। यह बीमारी मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी और जूं जैसे खून चूसने वाले कीटों के माध्यम से फैलती है। उन्होंने बताया कि लंपी रोग से प्रभावित पशुओं में त्वचा पर गांठें, तेज बुखार, दूध उत्पादन में कमी, आंख-नाक से पानी आना, लार टपकना, पैरों में सूजन और लसीका ग्रंथियों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। सीवीओ डॉ. शर्मा ने बताया कि बीते वर्ष जिले में लंपी रोग का प्रकोप तेजी से फैला था, हालांकि समय पर किए गए टीकाकरण से बीमारी की रोकथाम में मदद मिली।

उत्तर रेलवे

इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा आमंत्रण

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल सामग्री प्रबंधक, उत्तर रेलवे मुरादाबाद-244001 द्वारा निविदाकर्ताओं से निम्नलिखित मद के लिए इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रणाली के अन्तर्गत सेवाओं हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	निविदा सं.	माल का विवरण	मात्रा	बयाना राशि रु.	अनुमानित मूल्य रु.	निविदा खुलने की तिथि
01	GEM/ 2026/ B/ 7123640	सेवाओं के लिए अनुकूलित निविदा – विभिन्न श्रेणियों में 53 कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग जिनमें 19 सहायक कैंटीन कर्मचारी, 16 सामान्य सहायक सामान्य प्रशासनिक कर्मचारी और 18 गृह रखरखाव सहायक शामिल हैं। यह नियुक्ति ओक ग्रोव स्कूल के रखरखाव और देखभाल के लिए न्यूनतम मजदूरी पर की जाएगी।	01 Nos	3,31,460/-	1,65,72,984/-	21.02.2026 11:00:00

नोट: पूर्ण विवरण एवं निविदा शर्तें वेबसाइट www.gem.gov.in पर उपलब्ध हैं। सभी इच्छुक निविदाकर्ताओं को ई-निविदा में भाग लेने तथा पंजीकरण कराने के लिए भारत सरकार आईटी अधिनियम 2000 के तहत प्राधिकृत प्रमाणित एजेंसी से क्लास III डिजिटल प्रमाण पत्र, यदि पहले से प्राप्त नहीं किया है, प्राप्त मान्य होगा। मैन्युअल निविदा स्वीकृत नहीं की जायेगी।

पत्र सं.: 50-S/LP/2026 दिनांक: 02.02.2026 364/2026

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।

उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग

पत्रांकः- 356 / 18ए0सी0 दिनांकः- 02/02/2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

महा महिम राज्यपाल, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित कार्यों हेतु सील्ड निविदा दि0 09/02/2026 को अपराह्न 03:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 04/02/2026 से 09/02/2026 तक किसी भी कार्य दिवस में निम्नलिखित कार्यालयों से प्राप्त किये जा सकते है तथा दिनांक 11/02/2026 को अपराह्न 11:00 बजे तक इन्हीं कार्यालयों में डाले जा सकते हैं :-

1- अधीक्षण अभियन्ता, 12 वां वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
2- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा।
3- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन।
4- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, ऋषिकेश।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	धरोहर धनराशि (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	निविदा की वैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार में खोह नदी पर 100 मी0 विस्तार के बहुपाटान आर0सी0सी0 गर्डर गाड़ीघाट असुरक्षित सेतु के सुरक्षात्मक कार्य हेतु कर्टेनवाल तथा रिवर टैनिंग का निर्माण कार्य।	39000.00	1000+ जी0एस0टी0	30 दिन	01 माह	मार्ग कार्य में श्रेणी डी0 एवं उच्चतर।

निविदा दिनांक 11/02/2026 को पूर्वाह्न 3:00 बजे उपस्थित निविदादाताओं अथवा अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, दुगड्डा में कार्यालय में खोली जायेगी। अन्य शर्तें निविदा पत्र के साथ देखी जा सकेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

(इं0 निर्भय सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
दुगड्डा (गढ़वाल)

(1512/53)

संक्षिप्त समाचार

पहाड़ की पारंपरिक शैली में सुसज्जित प्रवेश द्वार का होगा निर्माण

श्रीनगर गढ़वाल : नगर निगम क्षेत्र के केवट मोहल्ले में जल्द ही पहाड़ की पारंपरिक शैली में सुसज्जित प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। इस द्वार के बनने से जहां मोहल्ले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, वहीं यह क्षेत्र की शोभा और सांस्कृतिक पहचान को भी नया आयाम देगा। वार्ड पार्षद शुभम प्रभाकर ने बताया कि नगर निगम की हाल ही में आयोजित बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे मंजूरी मिल चुकी है। कहा प्रवेश द्वार के निर्माण के बाद मोहल्ले में आने-जाने वाले लोगों व वाहनों पर नजर रखना आसान होगा। कहा, प्रस्तावित प्रवेश द्वार को पहाड़ की पारंपरिक कला व संस्कृति से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे यह द्वार अन्य मोहल्लों से अलग और आकर्षक नजर आएगा। पारंपरिक शैली में निर्मित यह प्रवेश द्वार मोहल्ले की पहचान बनेगा और क्षेत्र की सुंदरता में भी वृद्धि करेगा। कहा अब जल्द ही केवट मोहल्ले के प्रवेश द्वार का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। (एजेंसी)

ऑनलाइन कार्यों के लिए सुविधा न देने पर जताया आक्रोश

नई टिहरी। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी संगठन की बैठक में ऑनलाइन कार्यों को लिए लैपटॉप, मोबाइल, प्रिंटर देने की मांग प्रमुखता से छाई रही। लंबे समय से समस्याओं का निराकरण न होने पर चिंता व्यक्त की। कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की ग्रामीण क्षेत्र की विकास योजनाओं को धरातल उतारने का काम वीपीडीओ करते हैं लेकिन उनके पास संसाधनों की कमी है। संगठन के जिलाध्यक्ष पंकज उनियाल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कर्मियों ने समस्याएं रखी। कहा कि उन्हें अपने कार्य के साथ अन्य विभागों के भी अतिरिक्त कार्यों को भी पड़ना पड़ रहा है लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी बिना संसाधनों के सरकार की सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रार, यूसीसी का कार्य निबंधक का होता है लेकिन यह कार्य भी वीपीडीओ से ही कराया जा रहा है।

स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार न होने पर जताया दुख

नई टिहरी। नागरिक मंच नई टिहरी की बैठक में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं होने पर कड़ा आक्रोश जताया। लंबे समय से अस्पताल में तैनात सीएमएस का स्थानांतरण करने की मांग की। बौराड़ी में नागरिक मंच की बैठक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष भगवान चंद रमोला की अध्यक्षता में हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रमोला, महामंत्री जगजीत सिंह नेगी, संरक्षक सीपी डबराल ने कहा कि कई बार शिकायत किए जाने के बाद भी जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। अस्पताल की स्वास्थ्य सुविधाएं सुधारने करने ओर सीएमएस के स्थानांतरण की मांग की। बैठक में नई टिहरी–बौराड़ी की मुख्य सड़क से अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने, बौराड़ी स्थित मेगामार्ट के पास यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस जवान तैनात करने, नई टिहरी में व्यावसायिक गतिविधि बढ़ाने की मांग की गई। मंच पदाधिकारियों ने नगरवासियों के लिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने, सेक्टर के मुताबिक जमीन के खाते तैयार करने, ग्रीन बेल्ट पर भूखंड आवंटित करने का विरोध किया है। उन्होंने देहरादून से कोटीकॉलोनी के लिए संचालित हेली सेवा को रविवार को नई टिहरी के लिए संचालित करने, हेली सेवा संचालन के दौरान अप्रिय घटना को रोकने के लिए टिहरी झील क्षेत्र के आसपास होने वाली पैराग्लाइडिंग पर रोक लगाए जाने सहित आठ सूत्री मांगों का प्रस्ताव पास किया।

जंगली सुअरों ने बढ़ाई कफुल्टा के किसानों की मुसीबतें

नई टिहरी। जंगली सुअरों ने ग्राम पंचायत कफुल्टा के किसानों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वन विभाग के कार्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित कफुल्टा गांव में जंगली सुअर रात के समय खेतों में घुसकर आलू, मटर और लहसुन की नकदी फसलों को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में आलू, मटर और लहसुन की फसल इन दिनों तैयार हो चुकी है लेकिन जंगली सुअर झुंड बनाकर खेतों में घुस रहे हैं।

फसल को तहस नहस कर दे रहे हैं। ग्राम प्रधान प्रमिला देवी, काश्तकार जगत सिंह असवाल, अरविंद नौटियाल, भरत सिंह असवाल, रघुवीर सिंह असवाल, जयवीर सिंह असवाल, राकेश सिंह ने बताया कि जंगली सुअरों के कारण किसानों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां स्वच्छता अभियान की सशक्त वाहक, घर-घर पहुंचा रही जागरूकता का संदेश

आंगनबाड़ी से कार्यालयों तक स्वच्छता और शपथ का व्यापक अभियान

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में एवं जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया के नेतृत्व में जनपद पौड़ी गढ़वाल में 26 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक विशेष, व्यापक एवं सहभागितापूर्ण स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता को केवल सरकारी कार्यक्रम न मानकर जनभागीदारी से जुड़ा एक सतत सामाजिक आंदोलन बनाना है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेंद्र थपलियाल ने बताया कि अभियान के तहत आंगनबाड़ी परिसरों एवं आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई के साथ-साथ ग्रामीणों, महिलाओं एवं अभिभावकों को स्वच्छता के प्रति जागरुक करते हुए स्वच्छता की शपथ दिलायी जा रही है। वहीं जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालयों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा सफाई अभियान संचालित कर स्वच्छता की शपथ ली जा रही है, जिससे स्वच्छ वातावरण के प्रति सामूहिक जिम्मेदारी को बल मिल सके। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां स्वच्छता अभियान की सशक्त वाहक बनकर जनपद में जागरुकता का संदेश घर-घर तक पहुंचा रही हैं। सभी का प्रयास है कि स्वच्छता की यह पहल केवल अभियान तक सीमित न रहकर लोगों की जीवनशैली का हिस्सा बने। जिलाधिकारी ने कहा कि यह अभियान केवल एक माह की गतिविधि नहीं है, बल्कि स्वच्छ, स्वस्थ एवं पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज के निर्माण की दिशा में निरंतर चलने वाला प्रयास है। उन्होंने बताया कि अभियान की प्रभावी निगरानी के लिए प्रत्येक विकासखंड में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है तथा कूड़ा संग्रहण एवं निस्तारण व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 26 फरवरी के बाद भी स्वच्छता अभियान की यह पहल निरंतर जारी रहेगी, ताकि जनपद में स्वच्छता को स्थायी आदत के रूप में स्थापित किया जा सके।

महिला सशक्तिकरण की नई कहानी, ग्रोथ सेंटर से बदली आजीविका

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग के दूरस्थ क्षेत्र मक्कूमठ में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु एक आधुनिक ग्रोथ सेंटर की स्थापना की गई है।

यह ग्रोथ सेंटर राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत आस्था ग्राम संगठन से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान कर विकसित किया गया है। यहाँ महिलाएं स्थानीय उत्पादों से माल्टा, संतरा और बुरांश का जूस तैयार करने के साथ-साथ आम, मिर्च, लिंगुड़ा और आंवले के अचार का प्रसंस्करण कर रही हैं। महिलाओं के कार्य को और सशक्त बनाने के लिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत लगभग 15 लाख रुपये की लागत से प्रोसेसिंग यूनिट भी स्थापित की गई है। वर्तमान में इस ग्रोथ सेंटर में 10 महिलाएं नियमित रूप से कार्य कर रही हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि के साथ-साथ आत्मविश्वास और स्वावलंबन भी बढ़ा है। ऊखीमठ की खण्ड विकास अधिकारी अनुष्का ने बताया कि अभी तक इन महिलाओं ने 5 लाख तक की आय अर्जित की है उन्होंने कहा कि ब्लॉक की पूरी टीम स्थानीय महिलाओं के लिए हमेशा कार्य करती रहती हैं, आगे भी इस तरह के ग्रोथ सेंटर खोलने की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। यह पहल न केवल स्थानीय आजीविका को मजबूती दे रही है, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और स्वरोजगार का एक सफल मॉडल भी बनकर उभर रही है।

एलोपैथिक फार्मासिस्टों को नियुक्ति न होने पर आंदोलन की दी चेतावनी

श्रीनगर गढ़वाल : प्रदेश कांग्रेस सचिव सोशल मीडिया रमलाल नौटियाल ने सरकार से बेरोजगार एलोपैथिक फार्मासिस्टों को शीघ्र नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। कहा यदि सरकार ने मांग पर अमल नहीं किया तो उन्हें आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा। रमलाल नौटियाल ने कहा कि देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के बागी अस्पताल में गर्भवती की मौत के बाद टिहरी में एक और गर्भवती की मृत्यु होना प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जीवंत उदाहरण है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो सरकारी दावों की पोल खोलती हैं और यह सिद्ध करती हैं कि मौजूदा स्वास्थ्य ढांचा पूरी तरह विफल हो चुका है। कहा वर्ष 2006 में तत्कालीन राज्य सरकार ने उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत उपकेंद्रों में 539 पदों पर एलोपैथिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति की थी, जिससे ग्रामीण जनता को काफी राहत मिली थी। लेकिन भाजपा सरकार ने वर्ष 2021 में इन पदों को समाप्त कर दिया। विरोध के बावजूद पिछले चार वर्षों से सरकार इन पदों को पुनर्जीवित करने के नाम पर केवल आश्वासन देकर बेरोजगार फार्मासिस्टों को गुमराह कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से शीघ्र फार्मासिस्टों की नियुक्ति दिए जाने और आईपीएचएस मानकों में राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप बदलाव किया जाने की मांग की है। (एजेंसी)

विज्ञान प्रदर्शनी में अनंत ने मारी बाजी

श्रीनगर गढ़वाल : केंद्रीय विद्यालय संगठन के संभागीय कार्यालय देहरादून की ओर से आयोजित 53वीं क्षेत्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में केंद्रीय विद्यालय एसएसबी श्रीनगर के छात्र-छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विद्यालय का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में कक्षा 8 के छात्र अनंत रावत ने प्रथम स्थान, जबकि कक्षा 9 के छात्र शाश्वत बलोदी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। यह विज्ञान प्रदर्शनी 29 एवं 30 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय आईआईपी मोहकमपुर, देहरादून में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में अनंत रावत ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थीम के अंतर्गत इको फ्रेंडली कृषि मॉडल प्रस्तुत किया, जिसकी निर्णायकों ने अत्यंत सराहा की। वहीं शाश्वत बलोदी ने ग्रीन एनर्जी प्रोग्राम के तहत पोर्टेबल सोलर पावर्ड मोबाइल चार्जर का मॉडल बनाकर प्रस्तुत किया। विद्यालय की प्राचार्य कृति ने विजेता छात्रों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं मार्गदर्शक शिक्षकों को भी इस सफलता के लिए बधाई दी। (एजेंसी)

ग्रामीणों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण करें : एसडीएम

न्याय पंचायत बगेली में आयोजित हुआ बहुउद्देश्यीय शिविर, 19 शिकायतें दर्ज

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में जनपद की सभी न्याय पंचायतों में आयोजित हो रहे बहुउद्देश्यीय शिविर ग्रामीणों के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। इन शिविरों के जरिए आमजन को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलने के साथ ही उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को विकासखंड थलीसैंण की न्याय पंचायत बगेली में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया।शिविर में जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत के आकस्मिक निधन पर दो मिनट का मौन रखा गया। जिसके चलते कार्यक्रम को सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया।

शिविर में कुल 19 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। शिविर की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी थलीसैंण कृष्णा त्रिपाठी ने की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उपजिलाधिकारी ने कहा कि बहुउद्देशीय शिविरों से ग्रामीणों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार मुख्यालय न जाना पड़े और योजनाओं का लाभ गांव में ही उपलब्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बाल विकास, वन, राजस्व, कृषि, उद्यान, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पशुपालन, एनआरएलएम, रीप सहित कुल 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए। विभागीय अधिकारियों ने न केवल योजनाओं की जानकारी दी, बल्कि पात्र लोगों को मौके पर ही लाभान्वित भी किया। इस अवसर पर शिविर के नोडल अधिकारी एवं अधिशासी अभियंता विद्युत नैनीडांडा देवराज सिंह, एसडीओ थलीसैंण अभिषेक नेगी, नायब तहसीलदार सुदामा सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

छात्रों को कानूनों के प्रति किया जागरूक

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जिला परिवीक्षा अधिकारी अरविंद सिंह के निर्देशन में देवभूमि पब्लिक स्कूल, नकोट (श्रीनगर) में बाल संरक्षण एवं साइबर सुरक्षा पर जनजागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को बाल अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, साइबर अपराधों से बचाव तथा बाल संरक्षण से जुड़े विभिन्न कानूनों के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम में महिला थाना की पुलिस इंस्पेक्टर प्रियंका भारद्वाज द्वारा पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के साथ होने वाले अपराधों, उनके कानूनी अधिकारों तथा ऐसे मामलों में मिलने वाली कानूनी सहायता एवं संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। उन्होंने विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की असहज स्थिति में निडर होकर शिकायत दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया। थाना श्रीनगर से इंस्पेक्टर विमल कुमार ने वर्तमान समय में बढ़ते साइबर अपराधों, सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव तथा डिजिटल सतर्कता के संबंध में जानकारी प्रदान की तथा साइबर हेल्पलाइन नंबर 1030 के महत्व के बारे में बताया। कार्यक्रम में पूजा नेगी द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के माध्यम से बच्चों को मिलने वाली सहायता, इसकी कार्यप्रणाली तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान सिंह ने सभी अतिथियों एवं वक्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए विद्यार्थियों से अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, गलत के विरुद्ध आवाज उठाने तथा समाज में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रज्ञा नैथानी, निखिल डेविड, पूजा नेगी, बाल कल्याण समिति की सदस्य सुनीता भट्ट सहित चाइल्ड हेल्पलाइन एवं संबंधित विभागों के अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्राथमिकता के आधार पर अधिकारी करें शिकायतों का निस्तारण

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनकल्याणकारी पहल जन-जन की सरकार के अंतर्गत विकासखंड पोखरी की न्याय पंचायत थालाबैंड पोखरी में सोमवार को युगल किशोर पंत, सचिव, सिंचाई एवं संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाना तथा स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना रहा। इस दौरान शिविर में 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से आमजन को सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में लगभग 500 से अधिक ग्रामीणों ने प्रतिभाग कर विभागीय स्टॉलों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। इस दौरान ग्रामीणों द्वारा सड़क, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बंदर एवं लंगूरों से फसलों को हो रहे नुकसान से संबंधित कुल 33 शिकायतें दर्ज कराई जिनमें से 29 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस दौरान शिविर की अध्यक्षता कर रहे युगल किशोर पंत, सचिव, सिंचाई एवं संस्कृति ने शिकायतों का निस्तारण करते हुये सभी अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्रामीणों की शिकायतों एवं समस्याओं का निस्तारण एक निश्चित समय एवं गुणवत्ता करें।

दो दिव्यांग खिलाड़ियों का स्पेशल ओलंपिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में चयन

कीर्तिनगर : विकासखंड कीर्तिनगर क्षेत्र के दो दिव्यांग प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन स्पेशल ओलंपिक भारत की राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता रोहतक (हरियाणा) में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भारत सरकार की ओर से तीन से छह फरवरी तक आयोजित की जाएगी, जिसमें देशभर से चयनित खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। चयनित खिलाड़ियों में राजेंद्र सिंह, निवासी ग्राम खोला कड़ाकोट व राहुल रतूड़ी, निवासी ग्राम पाली डागचौरा शामिल हैं। दोनों खिलाड़ी एथलेटिक्स विधा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय स्पेशल ओलंपिक प्रतियोगिता जो हाल ही में ऋषिकेश में आयोजित की गई थी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ है। अब यह खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर राजकीय इंटर कॉलेज, खोला कड़ाकोट के व्यायाम शिक्षक सतीश बलूनी व देहरादून के जगदीश चौहान के मार्गदर्शन में प्रतिभाग करेंगे। बलूनी ने बताया कि दोनों खिलाड़ी पूर्व में राजकीय इंटर कॉलेज खोला कड़ाकोट व राजकीय इंटर कॉलेज डागचौरा के छात्र रहे हैं। इन खिलाड़ियों के राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, खंड शिक्षा अधिकारी, खेल प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए खिलाड़ियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। (एजेंसी)

पदम सिंह ने नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीते पदक

श्रीनगर गढ़वाल : अजमेर (राजस्थान) के पटेल सिंथेटिक स्टेडियम में आयोजित 7वीं नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में उत्तराखंड के एथलीट पदम सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 800 मी. दौड़ में रजत तथा 1600 मी. दौड़ में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता से लौटने के बाद नगर निगम क्षेत्र के बैद्यगांव बिलकेदार निवासी पदम सिंह गुसांई ने बताया कि यह प्रतियोगिता 31 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आयोजित की गई थी। जिसमें देशभर के 25 राज्यों से 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। भारतीय सेना से सूबेदार पद से सेवानिवृत्त पदम सिंह वर्तमान में बीएसएनएल में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि वह अपने दैनिक कार्यों के अलावा स्वयं नियमित अभ्यास करने के साथ-साथ विष्णुलोक, देहरादून में रहकर युवाओं को भी प्रशिक्षण देकर खेलों के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

रंगारंग कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया वार्षिकोत्सव

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : नागेंद्र इंटर कॉलेज बजीरा का वार्षिकोत्सव रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विधायक भरत सिंह चौधरी ने विद्यालय के कनिष्ठ सहायक सतीश राणा द्वारा निर्मित भारत माता की सात फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया।

इससे पूर्व विधायक श्री चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र-छात्राओं को बेहतर भविष्य निर्माण के टिप्स दिए। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बजीरा के धरगाढ मथ्यागांव रणोंखर्क मोटर मार्ग निर्माण के लिए कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत फेज-4 में मोटर मार्ग निर्माण के लिए टेण्डर प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा। उन्होंने विद्यालय को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य बजीरा नीता बुटोला ने जिला पंचायत निधि से एक कक्षा कक्ष निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की। इस अवसर पर अध्यक्ष जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम कठैत, रावल नागेंद्र देवता बसंत सिंह राणा, भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष वाचस्पति सेमवाल, राजकीय शिक्षक संघ के पूर्व मण्डलीय मंत्री शिव सिंह नेगी, भाजपा मण्डल अध्यक्ष मेहरवान सिंह रावत, प्रधानाचार्य शहीद राय सिंह बंगारी इण्टर कॉलेज चमालकोट गोविन्द सिंह नेगी, प्रधानाचार्य बीरेंद्र सिंह राणा, पूर्व सैनिक संगठन के जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल भण्डारी, सूबेदार मेजर महावीर सिंह नेगी, जिला पंचायत सदस्य बजीरा वार्ड नीता बुटोला, प्रबंधक भगत सिंह पुण्डीर, गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष प्रदीप पंवार, गम्भीर सिंह कैंतुरा, धूम सिंह भण्डारी, जितेन्द्र सिंह नेगी, बलवीर सिंह नेगी, प्रबंध समिति उपाध्यक्ष दिलवरी लाल, महिला मंगल दल अध्यक्ष जखोली सम्मा देवी, महिला मंगल दल अध्यक्ष बजीरा दीना देवी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने किया श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा विकसित श्रमिक प्रशिक्षण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पंजीकृत श्रमिकों एवं उनके आश्रित परिवारजनों के कौशल विकास को पारदर्शी, प्रभावी एवं तकनीक-आधारित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार श्रमिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पूर्णतः ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कौशल प्रशिक्षण के उपरांत श्रमिकों के सर्वांगीण विकास से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर भी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही राज्य के उद्यमियों से कौशल आवश्यकताओं के संबंध में नियमित फीडबैक लिया जाए, ताकि प्रशिक्षण को रोजगार से बेहतर रूप से जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन आदि व्यवसायों में प्रशिक्षण पर विशेष बल देने के निर्देश दिए, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति स्थानीय श्रमिकों से हो सके और रोजगार के अवसर बढ़ें। इससे क्षेत्रीय जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने में भी सहायता मिलेगी। श्रम विभाग के सचिव डॉ. श्रीधर बाबू अद्दंकी ने बताया कि विभाग द्वारा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी योजनाओं को अधिक पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में श्रमायुक्त पी.सी. दुमका, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

टीबी के खात्मे को चलेगा 100 दिन का अभियान

जयन्त प्रतिनिधि। रूद्रप्रयाग : क्षय रोग के खात्मे के लिए स्वास्थ्य विभाग विभाग के तत्वावधान में 100 दिवसीय नि-क्षय शिविर अभियान चलाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान के तहत फरवरी व मार्च के लिए कैंप का रोस्टर जारी कर दिया है। जिला क्षय अधिकारी डॉ. चौधरी ने बताया कि 100 दिवसीय नि-क्षय शिविर अभियान के तहत टीबी रोग को लेकर संवदेनशील आबादी (पूर्व टीबी से पीड़ित मरीजों, टीबी रोगियों के घरेलू संपर्कजनों, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, कुपोषित, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों तथा टीबी को लेकर उच्च जोखिम वाले चिन्हित गांवों में 14 वर्ष से अधिक समस्त आबादी) में नि-क्षय शिविर आयोजित कर रोगियों को खोजने के प्रयास तेज करने सहित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही सेवाओं की पहुंच में और अधिक सुधार किया जाएगा। टीबी केसों की खोज के तहत स्क्रीनिंग, एक्सरे एवं बलगम जांच की जाएगी, साथ-साथ शीघ्र निदान, शीघ्र उपचार आरंभ करने व रोगियों को पोषण संबंधित सहायता में शामिल करने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने बताया अभियान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है, जिसके तहत जिला, ब्लाक व स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर चिकित्सकों, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, एनटीईपी कार्मिकों सहित स्वास्थ्य कर्मियों को संवेदीकृत करने के साथ-साथ पहले 60 दिन का रोस्टर तैयार कर दिया गया है।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail:
nagendra.uniyal@gmail.com